(c) and (d) Bironkhel has not been connected on STD due to non-availability of stable media. Bironkhel is planned to be provided with stable media by using MCPC VSAT uring 1997-98. With this STD would be provided for Bironkhal and the village Baijrao will get STD through Bironkhel. Surkai village will get through Sunsi Exchange which is also planned connectively through MCPC VSAT during this financial year, 1997-98.

Expansion of Nalanda Telephone Exchange

798. SHRI RAJ NATH SINGH: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that capacity of the telephone exchange at Nalanda, an internationally renowned historical place is very low and it is manned only by a fourth grade employees;

(b) if so, whether Government propose to expand the capacity of the above exchange from the existing 128 C-DoT to 256 C-DoT;

(c) if so, by when the expansion work is likely to be under taken; and

(d) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) The capacity of the telephone exchange working at Nalanda is adequate for the present i.e. 96 lines. This exchange is manned by a fourth grade employee only for routine jobs. The technical operation and maintenance of this exchange are controlled by a technician and a JTO.

(b) and (c) It is planning to replace the existing 128P C-DOT exchange with 256P C-DOT exchange during 1997-98.

(d) Does not arise.

Better Wireless Local Loop system

799. SHRI E. BALANANDAN: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ITI based venture developed better Wireless Local Loop (WLL) system with 10,000 subscribers per sq. km. using the cordect, a system developed by the IIT based venture; and

(b) if sp, whether DOT has conducted any test check of the system?

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS (SHRI BENI PRASAD VARMA): (a) No, Sir.

(b) Question does not arise.

ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा के विस्तार हेतु अलग बजट/लक्ष्य निर्धारित किया जाना

800. **श्री एस०एस० सुरजेवाला:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन सुविधा के विस्तार हेतु अलग बजट/लक्ष्य निर्धारित करने तथा इसे एक दूरसंचार जिला/जोन/राज्य के लिए निर्धारित विशेष धनराशि/लक्ष्यों के संयुक्त आवंटन से अलग करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक विशेष क्षेत्र के लिए बजटीय आबंटन तथा लक्ष्य का अक्सर शहरी/अर्ध शहरी क्षेत्रों के लिए उपयोग किया जाता है और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी जाती है; और

(ङ) गत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति हुई है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): (क) दूरसंचार विभाग में टेलीफोन सुविधा का ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार करने के लिए पृथक बजट/लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी प्रक्रिया पहले से ही मौजूद है। इसके अलावा, वार्षिक योजनाओं तथा पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों (प्रत्येक ग्राम को प्रदान किया जाने वाला) के लिए पृथक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। 1997-98 के लिए ग्रामीण क्षेत्र हेतु बजट

आबंटन 1700/- करोड़ रु० है। 1997-98 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र हेतु टेलीफोन का लक्ष्य निम्नानुसार है:—

ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (अदद) :	83,000
छोटे एवं मध्यम आकार के एक्सचेंज (सकल लाइन):	15,00000

(मुख्य रूप से ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाले)

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) ग्रामीण क्षेत्र के अल्प प्रयुक्त बजट का प्रयोग दूरसंचार विकास हेतु सामान्य क्षेत्र में प्रयोग किया गया था। तथापि, ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा नहीं की जा रही है तथा इनमें दूरसंचार सेवाओं के तीव्र विस्तार के लिए निरन्तर प्रयास किया जा रहा है।

(क) ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वी पी टी)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1994-95	50000	47604
1995-96	105000	31496
1996-97	75000	56719

(ख) छोटे तथा मध्यम आकार के एक्सचेंज

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धियां
1994-95	750000	1186690
1995-96	1050000	907641
19096-97	1054000	1202092

मोबाइल और सेलूलर सुविधाएं

801. **श्री राघवजी:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के किन-किन शहरों में मोबाइल/सेलूलर फोन की सुविधा उपलब्ध है तथा ये सुविधाएं वहां किन-किन तारीखों से उपलब्ध करायी गयी है;

(ख) क्या यह सेवा निजी क्षेत्र द्वारा भी उपलब्ध करायी जा रही है, यदि हां, तो इस सेवा का संचालन करने के लिए कंपनियों को कितनी-कितनी राशि का और कितनी-कितनी अवधि का, किन-किन स्थानों के लिए ठेका दिया गया है; और

(ग) 30 जून, 1997 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक शहर में मोबाइल फोनों की संख्या कितनी-कितनी है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा): जिन नगरों में सेलूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा उपलब्ध है और जिन तारीखों से यह सेवा उपलब्ध है, उसका ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ख) जी हां। कम्पनियों के नाम उनके सेवा क्षेत्रों सहित अनुबंध-I में दिए गए हैं सभी मामलों में लाइसेंसों की अवधि 10 वर्ष है। दूरसंचार सर्किलों तथा महानगरों के संबंध में लाइसेंस शुल्क विवरण-II में दिया गया है। (नीचे देखिये)

(ग) महानगरों तथा दूरसंचार सर्किलों में उपभोक्ताओं की संख्या, जहां यह सेवा शुरू की गई है, विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रचालन हेतु लाइसेंस प्राप्त कंपनियों तथा सेवा क्षेत्रों के नाम तथा उन शहरों के नाम जिनमें यह सेवा उपलब्ध है और जिस तारीख से उपलब्ध है:—

क्रम सं०	कंपनी का नाम	सेवा क्षेत्र दूरसंचार सर्किल/महानगर	शहर का नाम	दिनांक/मास/वर्ष
1.	मै० टाटा कम्युनिकशंस प्रा० लि०	आन्ध्र प्रदेश	हैदराबाद	11.12.96
			विजयवाड़ा	08.04.97
			गुंटूर	08.04.97